ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

3248. **श्री राम नरेश यादव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु सरकार कौन-कौन से नये कदम उठा रही है तथा इस संबंध में क्षेत्रवार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास की गति मन्द होने के कारण वहां के लोग शहरों में आ रहे है ;

(ग) यदि हा, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आकर्षक रोजगार प्रदान करने हेतु तैयार की गई नई योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त समस्या पर कब तक काबू पा लिए जाने की सभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) और (ग) जवाहर रोजगार योजना, दिल्ली और चण्डीगढ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अन्य रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाना है। सुनिश्चित रोजगार योजना नामक एक नयी योजना देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों, मरूक्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित 257 जिलों के चयनित 1755 पिछड़े खण्डों में शुरू की गई है जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन में है। चालू वर्ष अर्थात् 1993-94 के लिए नई योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय बजट में 600.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शारीरिक रूप से सक्षम लोगों को, जिन्हें काम की आवश्यकता है और जो काम करना चाहते हैं लेकिन जिन्हें गैर-कृषि मौसम के दौरान काम नहीं मिलता है, को 100 दिन का श्रमिक रोजगार मुहैया कराना है। (राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं) **(नीचे देखिए)**

इसके अतिरिक्त सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में चयन किये गये 120 पिछड़े जिलों में गहन जवाहर रोजगार योजना भी कार्यान्वित की है जहां बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले लोगों की बहुतायात है। चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान इस गहन जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए 702.56 करोड़ रुपए का केन्द्रीय आवंटन किया गया है।

(ख) और (ग) : यह सही है कि समय-समय पर शुरू किये गये विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं लेकिन यह महसूस किया गया है कि सुनिश्चित रोजगार योजना के गति प्राप्त कर लेने के बाद गांवों से पलायन की समस्या में काफी हद तक कमी आयेगी ;

विवरण

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कवर किये गये खंडों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कवर किये गये खंड़ों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	120
2	अरूणाचल प्रदेश	48
3	असम	69
4	बिहार	157
5	गुजरात	97
6	हरियाणा	44
7	हिमाचल प्रदेश	7
8	जम्मू व कश्मीर	34
9	कर्नाटक	94
10	केरल	21
11	मध्य प्रदेश	223
12	महाराष्ट्र	114
13	मणिपुर	22
14	मेघालय	32
15	मिजोरम	20
16	नागालैंड	28
17	उड़ीसा	143
18	राजस्थान	122
19	सिक्किम	4

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कवर किये गये खंडों की संख्या
20	तमिलनाडु	56
21	त्रिपुरा	18
22	उत्तर प्रदेश	145
23	पश्चिम बंगाल	128
24	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
25	दादर व नगर हवेली	1
26	दमन व दीव	1
27	लक्षद्वीप	5
	योग :	1755

Assistance by Banks under IRDP

3249. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of beneficiaries assisted by the banks under the Integrated Rural Development Programme (IRDP) during the last three years, year-wise;

(b) the percentage of the beneficiaries who belonged to Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the I.R.D.P. during the same period;

(c) the percentage of advances of public Sector banks of their net bank credit to weaker sections during the same period;

(d) whether it is a fact that there has been large scale misutilisation and default of rural banks credit during the same period; and

(e) if so, the details thereof and the reasons therefor and what corrective steps Government have taken/propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) Information is given in the Statement, (*See below*).

(c) As per information in the R.B.I. Reports, the percentage of advances of Public Sector banks of their net bank credit to weaker sections during the last three years was 9.7% (1990-91), 9.7% (1991-92) and 8.9 per cent (1992-93).

(d) and (e) The evaluation study conducted by Government/ Reserve Bank of India does not indicate large scale misutilisation of funds. The recovery performance was however not